भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2117

(दिनांक 20.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

क्षेत्रीय फिल्म निर्माता

2117. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और आवश्यक सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार की गुजरात में फिल्म उद्योग के विकास और समर्थन के लिए कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), केंद्रीय क्षेत्र की योजना "फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)" के तहत भारत और विदेश, दोनों के निजी फिल्म निर्माताओं के साथ साझेदारी में अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों का सह-निर्माण तथा नवोदित फिल्म निर्माताओं की पहली फीचर फिल्म का निर्माण कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों का निर्माण और सह-निर्माण करता है।

सरकार, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से प्रति वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ-साथ गोवा में फिल्म बाजार का आयोजन कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से, फिल्म बाजार में प्रमुख राज्यों के संबंधित फिल्म कार्यालयों के साथ इन राज्यों की भागीदारी देखी गई है ताकि वे अपने प्रमुख स्थानों और दिए जा रहे प्रोत्साहनों को भारत और विदेश के विभिन्न प्रमुख फिल्म निर्माताओं के समक्ष प्रदर्शित कर सकें।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना की है जो ऑनलाइन सिंगल विंडो सुविधा और निकासी तंत्र के लिए उत्तरदायी है जो भारत में फिल्मांकन/शूटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाता है। फिल्म सुविधा कार्यालय, क्षेत्रीय फिल्म उद्योग सहित फिल्म उद्योग के विकास और समर्थन के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए, नियमित रूप से गुजरात राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नोडल अधिकारियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से संवाद करता है।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य (एमएफएफएस) पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत एक श्रेणी के रूप में शुरू किया गया है ताकि राज्य सरकारों को फिल्म अनुकूल माहौल बनाने के लिए और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एफएफओ द्वारा निष्पादित पुरस्कार राज्य सरकारों को प्रेरित करने और उनके राज्यों में फिल्मांकन को आसान बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन राज्यों को अब तक सम्मानित किया गया है - गुजरात (2015), उत्तर प्रदेश (2016, विशेष उल्लेख 2020), मध्य प्रदेश (2017, 2019 और 2020), उत्तराखंड (2018, विशेष उल्लेख 2020) और सिक्किम (2019)।

उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित 36 राज्य सरकारों में नोडल अधिकारियों का एक संसक्त इकोसिस्टम भी स्थापित किया गया है ताकि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में फिल्मांकन की अनुमति दी जा सके और फिल्मांकन में आसानी सुनिश्चित की जा सके।

*****